



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

No. 117]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2003/श्रावण 1, 1925  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2003/SRAVANA 1, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जुलाई, 2003

सं. टीएएमपी/103/2001-सीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा हल्दिया में कोलकाता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों की वर्तमान दर अनुसूची की वैधता बढ़वाने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास के प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेशों के अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी /103/2001- सीपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

आवेदक

आदेश

(जुलाई, 2003 के 8 वें दिन पारित)

यह प्रकरण हल्दिया में भूमि और भवनों हेतु वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता 31 दिसम्बर 2003 तक या संशोधित किराया अनुसूची की अधिसूचना की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़वाने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. केओपीटी ने अक्टूबर 2002 में, 2 दिसम्बर 2002 से एक वर्ष के लिए वैधता बढ़वाने के लिए इस निवेदन के साथ अनुरोध किया था कि किराया अनुसूची बहुत अच्छी तरह काम कर रही थी और इस अवस्था में ऊपर की दिशा में संशोधन यातायात की बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। पत्तन के वाणिज्यिक निर्णय को मान्यता प्रदान करते हुए इस प्राधिकरण ने वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता 2 दिसम्बर 2002 से 30 जून 2003 तक की अवधि के लिए बढ़ाते हुए 4 फरवरी 2003 को एक आदेश इस शर्त के अधीन पारित किया कि इसके बाद वैधता को, वर्तमान दर-संरचना की व्यापक समीक्षा किए बिना और अधिक विस्तार नहीं दिया जाएगा। केओपीटी को सलाह दी गई थी कि वह वर्तमान दरों की ताजा समीक्षा के लिए 30 अप्रैल 2003 तक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दे ताकि 30 जून 2003 को वर्तमान दरों की वैधता समाप्त होने से पर्याप्त समय पहले नई दरें अधिसूचित की जा सकें।

3.1. केओपीटी ने अब, वर्तमान किराया सूची की वैधता को 31 दिसम्बर 2003 तक या संशोधित किराया अनुसूची की अधिसूचना की तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार देने का अनुरोध किया है।

3.2. केओपीटी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत किए हैं :-

- (i) इंडियन पोर्ट्स असोसिएशन (आईपीए) ने हाल ही में भूमि और भवनों का ताजा व्यापक मूल्यांकन करने के बाद मसौदा मूल्यांकन रिपोर्ट और प्रस्तावित दर संरचना प्रस्तुत की है।
- (ii) सरकारी मार्गदर्शों के अनुसार, मूल्यांकन रिपोर्ट और प्रस्तावित दर संरचना की जांच पड़ताल, अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति में नौवहन मंत्रालय और राज्य प्राधिकरणों के अधिकारी हैं।
- (iii) समिति द्वारा इस प्रकार संस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट और प्रस्तावित दर संरचना न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित की जानी है और इसके बाद इसे अनुमोदन के लिए टीएएमपी के पास प्रस्तुत किया जाना है।
- (iv) इस कवायद के पूर्ण होने में समय लगेगा और समिति के उन सदस्यों की उपलब्धता जो केओपीटी से इतर संगठनों के अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण हैं।
- (v) अपने अधिकतम प्रयासों के बावजूद, केओपीटी टीएएमपी द्वारा निर्धारित समय सीमा में किराया अनुसूची की समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत न कर सका। केओपीटी, टीएएमपी द्वारा अनुमोदन के लिए अपना प्रस्ताव 31 जुलाई 2003 तक प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है।

4. यह महत्वपूर्ण है कि केओपीटी में भूमि और भवनों का ताजा व्यापक मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका है। संबंधित रिपोर्ट और नई दर संरचना उसके विचाराधीन है। यहां इस बात को मानना होगा कि सरकारी मार्गदर्शों में विनिर्दिष्ट प्रक्रियात्मक पहलुओं को छोड़ा नहीं जा सकता। पत्तन ने आश्वासन दिया है कि वह अपना प्रस्ताव 31 जुलाई 2003 तक प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम प्रयास कर रहा है। किसी भी हालत में, 30 जून 2003 के बाद भूमि और भवनों के पट्टा किरायों के लिए रिक्तता नहीं रह सकती। ऐसा होते हुए, वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को 30 जून 2003 से आगे विस्तार देने हेतु केओपीटी के अनुरोध को स्वीकृति प्रदान करना अपरिहार्य हो जाता है।

5. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण, हल्दिया में केओपीटी की भूमि और भवनों हेतु वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता के विस्तार को, 31 दिसम्बर 2003 तक या प्राधिकरण द्वारा संशोधित किराया अनुसूची की अधिसूचना की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुमोदन प्रदान करता है। केओपीटी को सलाह दी जाती है कि वह अपना संशोधित प्रस्ताव अधिकतम 30 सितम्बर 2003 तक अवश्य प्रस्तुत करे।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003/असा.]

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 17th July, 2003

**No. TAMP/103/2001-CPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Kolkata Port Trust for extension of the validity of the existing schedule of rates for the lands and buildings of the Kolkata Port Trust at Haldia as in the Order appended hereto.

#### SCHEDULE

**Case No. TAMP/103/2001 - CPT**

The Kolkata Port Trust

----

Applicant

#### ORDER

(Passed on this 8th day of July 2003)

This case relates to a proposal received from the Kolkata Port Trust (KOPT) for extension of the existing Rent Schedule for lands and buildings at Haldia upto 31 December 2003 or the date of Notification of the revised Rent Schedule whichever is earlier.

2. In October 2002, the KOPT had requested for an extension of the validity by one year with effect from 2 December 2002 praying that the Rent Schedule was working well and any upward revision at that stage would affect the traffic growth. Recognising the commercial judgement of the port, this Authority passed an Order on 4 February 2003 approving extension of the validity of the existing rent schedule for a further period from 2 December 2002 to 30 June 2003 subject to the condition that no further extension of the validity period would be allowed without undertaking a comprehensive review of the existing rate structure. The KOPT was also advised to submit its proposal for a fresh review of the existing rates by 30 April 2003 so that new rates could be notified well in time before expiry of the validity of the existing rates on 30 June 2003.

3.1. The KOPT has now requested for an extension of the validity period of the existing Rent Schedule upto 31 December 2003 or the date of Notification of the revised Rent Schedule, whichever is earlier.

3.2. The KOPT has brought out the following points in support of its proposal:

- (i). The Indian Ports Association (IPA) has recently submitted the Draft Valuation Report as well as proposed rate structure after undertaking fresh comprehensive valuation of land and buildings.
- (ii). As per the Government guidelines, the Valuation Report and the proposed rate structure are to be examined by a Committee headed by the Chairman. The Committee consists of officials of Ministry of Shipping and State Authorities.
- (iii). The Board of Trustees has to approve the Valuation Report and the proposed rate structure so recommended by the Committee and then submit to TAMP for approval.
- (iv). The completion of the exercise is time consuming and the availability of Committee Members who are officials other than of the KOPT is important.
- (v). Despite their best efforts, the KOPT could not submit its proposal for revision of rent schedule within the time limit stipulated by the TAMP. The KOPT is trying to submit the proposal by 31 July 2003 for approval of TAMP.

4. It is significant that a fresh comprehensive valuation of land and buildings has already been done at KOPT. The relevant report and new rate structure are under its consideration. It is to be recognised that the procedural aspects specified in the Government guidelines cannot be dispensed with. The port has also assured that it is putting its best efforts to submit the proposal by 31 July 2003. In any case, there cannot be a vacuum in lease rentals for land and buildings after 30 June 2003. That being so, it is inevitable to accede to the request of the KOPT to extend the validity of the existing Rent Schedule beyond 30 June 2003.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves extension of the validity of the existing Rent Schedule for land and buildings of the KOPT at Haldia upto 31 December 2003 or the date of Notification of the revised Rent Schedule by this Authority, whichever is earlier. The KOPT is advised to file its revised proposal by 30 September 2003 latest.

A. L. BONGIRWAR, Chairman  
[ADVT III/IV/143/2003/Exty.]